Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Paper

झारखंड राज्य के संदर्भ में नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में जनजातीय शिक्षा का समग्र विकास: चुनौतियाँ, अवसर एवं क्रियान्वयन की संभावनाएँ

डॉ. सुजीत कुमार

सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, ज्योति प्रकाश महिला बी.एड. कॉलेज, डाल्टनगंज (मेदिनीनगर), पलामू जिला, झारखंड,भारत

Corresponding Author: * डॉ. सुजीत कुमार

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20509867

सारांश

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है। झारखंड जैसे जनजातीय बहुल राज्य में, जहाँ कुल जनसंख्या का लगभग 26.2% जनजातीय समुदाय से है (भारत की जनगणना, 2011), इस नीति का क्रियान्वयन अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं जटिल है। प्रस्तुत समीक्षा आलेख झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में NEP 2020 के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के समग्र विकास की संभावनाओं, चुनौतियों एवं क्रियान्वयन की व्यावहारिकता का विश्लेषण करता है। आलेख में मातृभाषा आधारित शिक्षा, डिजिटल अवसंरचना, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, शिक्षक प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी जैसे प्रमुख पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। शोध में द्वितीयक स्रोतों, नीति दस्तावेजों तथा उपलब्ध अध्ययनों का विश्लेषण किया गया है।

Manuscript Info.

- ✓ **ISSN No:** 2584-184X
- ✓ **Received:** 03-11-2025
- ✓ **Accepted:** 28-12-2025
- ✓ **Published:** 30-12-2025
- ✓ **MRR:3(12):**2025;144-148
- ✓ **©2025, All Rights Reserved.**
- ✓ **Peer Review Process:** Yes
- ✓ **Plagiarism Checked:** Yes

How To Cite

डॉ. सुजीत कुमार . झारखंड राज्य के संदर्भ में नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में जनजातीय शिक्षा का समग्र विकास: चुनौतियाँ, अवसर एवं क्रियान्वयन की संभावनाएँ. Indian J Mod Res Rev. 2025;3(12):144-148.

मुख्य शब्द: नई शिक्षा नीति 2020, जनजातीय शिक्षा, झारखंड, मातृभाषा शिक्षण, समावेशी शिक्षा, आदिवासी विकास

© 2025 डॉ. सुजीत कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

भारत एक विविधताओं से भरा राष्ट्र है, जहाँ 700 से अधिक जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। ये समुदाय अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान, भाषा, परंपरा एवं जीवनशैली के साथ देश की समृद्ध विरासत के वाहक हैं। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में ये समुदाय आज भी पिछड़ेपन के शिकार हैं। झारखंड राज्य, जो 2000 में बिहार से पृथक् होकर अस्तित्व में आया, देश का एक प्रमुख जनजातीय राज्य है। यहाँ संताल, मुंडा, हो, उराँव, भूमिज, खड़िया आदि अनेक जनजातीय समूह निवास करते हैं (झारखंड सरकार, 2023)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारत की शिक्षा व्यवस्था में 34 वर्षों बाद किया गया व्यापक परिवर्तन है। इस नीति में समावेशी, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना की गई है (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, 2020)। NEP 2020 में जनजातीय एवं वंचित समुदायों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है तथा मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा, स्थानीय संदर्भों पर आधारित पाठ्यक्रम एवं समुदाय की सहभागिता जैसे प्रावधान किए गए हैं। किंतु प्रश्न यह है कि झारखंड जैसे राज्य में, जहाँ भूगोल, संसाधन, भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता की जटिलताएँ विद्यमान हैं, इस नीति को धरातल पर कैसे उतारा जाए? प्रस्तुत आलेख इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास है। इसमें NEP 2020 के प्रमुख प्रावधानों का विश्लेषण, झारखंड की जनजातीय शिक्षा की वर्तमान स्थिति, चुनौतियाँ, अवसर एवं क्रियान्वयन की संभावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

2. नई शिक्षा नीति 2020: प्रमुख प्रावधान एवं जनजातीय परिप्रेक्ष्य

NEP 2020 में अनेक क्रांतिकारी प्रावधान हैं जो सीधे जनजातीय शिक्षा को प्रभावित करते हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (2020) के अनुसार यह नीति 5+3+3+4 की संरचनात्मक व्यवस्था प्रस्तावित करती है, जिसमें बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर विशेष बल दिया गया है।

2.1 मातृभाषा में शिक्षा

NEP 2020 का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रावधान यह है कि कम से कम कक्षा 5 तक तथा यथासंभव कक्षा 8 तक मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। झारखंड के लिए यह एक अत्यंत सकारात्मक प्रावधान है क्योंकि यहाँ के जनजातीय बच्चे प्रायः हिंदी या अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थता महसूस करते हैं। Panda और Mohanty (2009) ने अपने शोध में प्रमाणित किया है कि मातृभाषा में शिक्षा न केवल अधिगम को सुदृढ़ बनाती है, बल्कि विद्यार्थियों के ठहराव दर (retention rate) में भी उल्लेखनीय वृद्धि करती है।

2.2 समावेशी एवं समानतामूलक शिक्षा

नीति में विशेष शैक्षिक क्षेत्र (Special Education Zones - SEZ) की परिकल्पना की गई है जो जनजातीय, पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए समर्पित हैं (शिक्षा मंत्रालय, 2020) । सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (2022) की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन एवं शिक्षक तैनाती का प्रावधान किया गया है। Kumar (2021) का मत है कि SEZ की अवधारणा जनजातीय शिक्षा के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, बशर्ते इसे ईमानदारी से लागू किया जाए।

2.3 व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा

NEP 2020 में कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का प्रावधान है। इसमें स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों एवं परंपरागत ज्ञान के धनी व्यक्तियों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ने की बात कही गई है (शिक्षा मंत्रालय, 2020) । झारखंड के जनजातीय समुदायों की पारंपरिक कलाएँ, जैसे सोहराई एवं कोहबर चित्रकला, धातु शिल्प, वन-उत्पाद प्रसंस्करण आदि, व्यावसायिक शिक्षा के उत्कृष्ट अवसर प्रदान कर सकती हैं (झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, 2022) ।

2.4 प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल शिक्षा

नीति में DIKSHA, SWAYAM, e-Pathshala जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा की पहुँच बढ़ाने की योजना है (NCERT, 2021) । परंतु झारखंड के दूरदराज के जनजातीय क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। TRAI (2022) के आँकड़ों के अनुसार झारखंड में ग्रामीण ब्रॉडबैंड पहुँच राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है।

3. झारखंड में जनजातीय शिक्षा की वर्तमान स्थिति

झारखंड की जनजातीय शिक्षा का मानचित्र जटिल एवं बहुआयामी है। भारत की जनगणना (2011) के अनुसार, राज्य में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 57.1% है जो राज्य की समग्र साक्षरता दर 66.4% से काफी नीचे है।

3.1 नामांकन एवं ठहराव

UDISE+ रिपोर्ट (2022-23) के अनुसार, झारखंड में प्राथमिक स्तर पर जनजातीय बच्चों का नामांकन तो संतोषजनक है, परंतु माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर तक पहुँचते-पहुँचते ड्रॉपआउट दर चिंताजनक रूप से बढ़ जाती है। बालिकाओं की स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है। Ekka (2020) के अनुसार, आर्थिक दबाव, घरेलू जिम्मेदारियाँ, बाल विवाह तथा शिक्षा की प्रासंगिकता का अभाव, ड्रॉपआउट के प्रमुख कारण हैं।

3.2 शिक्षा की गुणवत्ता

ASER रिपोर्ट (2022) के अनुसार, झारखंड में कक्षा 5 के जनजातीय विद्यार्थियों में से केवल 38% ही कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ पाते हैं और 30% से भी कम बुनियादी गणित कर पाते हैं। यह आँकड़ा बताता है कि मात्र नामांकन से काम नहीं चलेगा, गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा। Ramachandran और Naorem (2013) का मत है कि शिक्षा की निम्न गुणवत्ता जनजातीय क्षेत्रों में सुधार के प्रयासों को बाधित करती है।

3.3 भाषाई चुनौती

झारखंड में संताली, मुंडारी, हो, कुड़ुख, खड़िया आदि अनेक जनजातीय भाषाएँ बोली जाती हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे स्कूल आने से पहले इन्हीं भाषाओं में संवाद करते हैं। जब उन्हें हिंदी या

© 2025 डॉ. सुजीत कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, तो उन्हें 'double transition' (भाषा और विषय दोनों साथ सीखना) की समस्या का सामना करना पड़ता है (Jhingran, 2009) । यह स्थिति अधिगम में गंभीर बाधा उत्पन्न करती है।

4. प्रमुख चुनौतियाँ

4.1 अवसंरचनात्मक चुनौतियाँ

झारखंड के अनेक जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय भवन, शौचालय, पेयजल एवं बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। DISE रिपोर्ट (2021) के अनुसार, राज्य के 23% से अधिक सरकारी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था नहीं है। दुर्गम पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में सड़क संपर्क की कमी के कारण बच्चों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। Singh (2019) का मत है कि बुनियादी सुविधाओं का अभाव शिक्षा के सभी सुधार प्रयासों को निरर्थक बना देता है।

4.2 शिक्षक संबंधी चुनौतियाँ

झारखंड में शिक्षकों की भारी कमी एक पुरानी समस्या है। झारखंड शिक्षा विभाग (2022) के आँकड़ों के अनुसार, एकल-शिक्षक विद्यालयों की संख्या अभी भी काफी है। इसके अतिरिक्त, अधिकांश शिक्षक जनजातीय भाषाओं से अनभिज्ञ हैं और स्थानीय संस्कृति के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। Beteille (2010) के अनुसार, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जनजातीय समुदायों की संस्कृति और शैक्षणिक आवश्यकताओं को शामिल न करना एक बड़ी कमी है। NEP 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इस रिक्तता को भरना अनिवार्य है।

4.3 सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ

जनजातीय परिवारों में गरीबी, कुपोषण एवं पलायन शिक्षा की निरंतरता में बाधक हैं। नीति आयोग (2022) की रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) में जनजातीय जिले सबसे नीचे हैं। मौसमी पलायन के दौरान अनेक बच्चे महीनों तक विद्यालय नहीं जा पाते। बाल श्रम भी एक गंभीर समस्या है जो शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने में बाधा डालती है।

4.4 सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक चुनौतियाँ

पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था (जैसे 'अखड़ा' - जनजातीय सामाजिक-शैक्षिक केंद्र) और आधुनिक विद्यालयी शिक्षा के बीच का द्वंद्व एक बड़ी चुनौती है। अनेक जनजातीय परिवार आधुनिक शिक्षा को अपनी संस्कृति और पहचान के लिए खतरा मानते हैं (Xaxa, 2014)। Devi (2021) के अध्ययन के अनुसार, यह सांस्कृतिक असंगति विद्यार्थियों में हीनभावना और अलगाव की भावना पैदा करती है, जो उनके शैक्षिक प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

4.5 डिजिटल विभाजन

NEP 2020 में प्रौद्योगिकी को शिक्षा का अभिन्न अंग माना गया है, किंतु झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल उपकरणों एवं इंटरनेट की पहुँच अत्यंत सीमित है। COVID-19 महामारी के दौरान यह विभाजन और अधिक स्पष्ट हो गया जब अनेक जनजातीय बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में भाग नहीं ले सके (UNICEF India, 2021)। TRAI (2022) के आँकड़े बताते हैं कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 4G कनेक्टिविटी का अभाव गंभीर बाधा है।

5. अवसर एवं संभावनाएँ

5.1 मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा (MLE) का विस्तार

NEP 2020 के अनुरूप झारखंड में मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा (Multilingual Education - MLE) का व्यापक अवसर है। राज्य में पहले से ही संताली, मुंडारी एवं हो भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा की कुछ पहल की जा चुकी हैं (झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, 2022) । Mohanty et al. (2010) का शोध सिद्ध करता है कि MLE न केवल जनजातीय बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाता है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान को भी सुरक्षित रखता है।
संताली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है और इसकी ओलचिकी लिपि है। यह एक बड़ा अवसर है कि इस भाषा में उच्च गुणवत्ता की शैक्षिक सामग्री तैयार की जाए और शिक्षकों को इस भाषा में प्रशिक्षित किया जाए।

5.2 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) की भूमिका

केंद्र सरकार ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के माध्यम से जनजातीय शिक्षा को सुदृढ़ करने की महत्त्वाकांक्षी योजना बनाई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय (2023) के अनुसार, 2023 तक देश में 740 EMRS स्थापित करने का लक्ष्य है। झारखंड में इनकी संख्या बढ़ाना और NEP 2020 के अनुरूप इनका पाठ्यक्रम तैयार करना एक महत्त्वपूर्ण अवसर है।

5.3 स्थानीय ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का एकीकरण

NEP 2020 में स्थानीय ज्ञान परंपराओं (Local Knowledge Systems) को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का प्रावधान है। झारखंड के जनजातीय समुदायों के पास वन प्रबंधन, जल संरक्षण, कृषि तकनीकें, औषधीय पौधों का ज्ञान, सामाजिक न्याय की परंपराएँ आदि के रूप में ज्ञान का अतुलनीय भंडार है (Samal, 2020) । इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से शिक्षा न केवल प्रासंगिक बनेगी बल्कि जनजातीय संस्कृति का संरक्षण भी होगा।

5.4 समुदाय की भागीदारी और ग्राम शिक्षा समिति

NEP 2020 में विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) एवं स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया गया है। झारखंड में पंचायत राज संस्थाएँ, जिनमें जनजातीय प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, शिक्षा के विकेंद्रीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। Govinda (2011) के अनुसार, समुदाय की सहभागिता से विद्यार्थियों की उपस्थिति, ठहराव एवं शैक्षिक गुणवत्ता में महत्त्वपूर्ण सुधार होता है।

5.5 व्यावसायिक शिक्षा एवं रोजगार

झारखंड खनिज संसाधनों से भरपूर है और यहाँ पर्यटन, वन-आधारित उद्योग, कृषि प्रसंस्करण आदि के क्षेत्र में रोजगार की

© 2025 डॉ. सुजीत कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

असीम संभावनाएँ हैं। NEP 2020 की व्यावसायिक शिक्षा के प्रावधानों का उपयोग करते हुए जनजातीय युवाओं को इन क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया जा सकता है (NSDC, 2022) । परंपरागत कलाओं जैसे सोहराई पेंटिंग, धोकरा शिल्प आदि को GI टैग प्राप्त है, जो इन्हें वैश्विक बाजार से जोड़ने का आधार बनाते हैं।

6. क्रियान्वयन की संभावनाएँ : एक व्यावहारिक दृष्टिकोण

6.1 शिक्षक प्रशिक्षण एवं पुनर्प्रशिक्षण

NEP 2020 के सफल क्रियान्वयन के लिए जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। इस प्रशिक्षण में स्थानीय भाषा का बुनियादी ज्ञान, जनजातीय संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता, बहुभाषी शिक्षण तकनीकें एवं प्रौद्योगिकी का समावेश होना चाहिए। झारखंड में SCERT एवं DIET संस्थाओं को इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभानी होगी (NCTE, 2020)।

6.2 जनजातीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री निर्माण

झारखंड की प्रमुख जनजातीय भाषाओं - संताली, मुंडारी, हो, कुड़ुख, खड़िया - में उच्च गुणवत्ता की शैक्षिक सामग्री (पाठ्यपुस्तकें, कार्यपुस्तिकाएँ, डिजिटल सामग्री) तैयार करना आवश्यक है। इस कार्य में स्थानीय विद्वानों, जनजातीय भाषा विशेषज्ञों एवं समुदाय के बुजुर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए (Mohanty, 2019)। संताल परगना एवं कोल्हान क्षेत्र में इस दिशा में कुछ सार्थक पहल हो चुकी है जिसे और विस्तार देने की आवश्यकता है।

6.3 डिजिटल अवसंरचना का विकास

झारखंड सरकार को NEP 2020 के डिजिटल शिक्षा के लक्ष्यों को साकार करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, सौर ऊर्जा चालित विद्यालय, टैबलेट/स्मार्टफोन आधारित शिक्षण तथा Community Learning Centres (CLC) की स्थापना करनी होगी। MeitY (2022) की 'डिजिटल इंडिया' पहल के साथ समन्वय कर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

6.4 बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान

जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति विशेष चिंता का विषय है। NEP 2020 में लैंगिक समावेशिता पर विशेष बल दिया गया है। इसके अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का विस्तार, छात्रवृत्ति योजनाओं का सुदृढ़ीकरण, स्थानीय महिला शिक्षकों की नियुक्ति तथा जागरूकता अभियानों के माध्यम से बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए (Nair, 2022)।

6.5 निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र

NEP 2020 के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र आवश्यक है। Sharma (2021) के अनुसार, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के लिए विशेष प्रदर्शन संकेतक (performance indicators) तैयार किए जाने चाहिए जो केवल नामांकन नहीं बल्कि सीखने की गुणवत्ता, सांस्कृतिक संवेदनशीलता एवं समुदाय की संतुष्टि को भी मापें। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् इस कार्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

7. विमर्श एवं विश्लेषण

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि NEP 2020 झारखंड की जनजातीय शिक्षा के लिए एक ऐतिहासिक अवसर प्रदान करती है। नीति के मूल्य - समता, समावेश, गुणवत्ता एवं सांस्कृतिक संवेदनशीलता - जनजातीय शिक्षा की आवश्यकताओं से मेल खाते हैं। परंतु नीति और व्यवहार के बीच की खाई को पाटना एक बड़ी चुनौती है।

Tilak (2020) का मत है कि भारत में शिक्षा नीतियाँ प्रायः अच्छी बनती हैं परंतु उनका क्रियान्वयन कमजोर रहता है। झारखंड में यह समस्या और भी जटिल है क्योंकि यहाँ संसाधनों की कमी, नौकरशाही की जड़ता एवं राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव क्रियान्वयन में बाधक रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ सकारात्मक संकेत भी हैं। झारखंड सरकार ने 'गुणवत्ता शिक्षा मिशन' एवं 'मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना' जैसी पहलें की हैं। NGOs एवं नागरिक समाज संगठन जैसे 'एकता परिषद्', 'आजीविका ब्यूरो' आदि जनजातीय शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक कार्य कर रहे हैं। इन प्रयासों को NEP 2020 के ढाँचे के साथ जोड़कर एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। Sundar (2016) के अनुसार, जनजातीय शिक्षा का प्रश्न केवल शिक्षाशास्त्र का नहीं है, यह अधिकार, न्याय एवं राजनीतिक सशक्तिकरण का भी प्रश्न है। अतः NEP 2020 के क्रियान्वयन में जनजातीय समुदायों की अपनी आवाज़ और एजेंसी को केंद्र में रखना अनिवार्य है।

8. निष्कर्ष

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 झारखंड की जनजातीय शिक्षा के लिए एक व्यापक अवसर का द्वार खोलती है। मातृभाषा में शिक्षा, स्थानीय ज्ञान का समावेश, व्यावसायिक कौशल विकास, समुदाय की सहभागिता एवं डिजिटल शिक्षा के प्रावधान जनजातीय बच्चों के शैक्षिक भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि - (1) जनजातीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता की शैक्षिक सामग्री तैयार की जाए; (2) शिक्षकों को सांस्कृतिक संवेदनशीलता एवं बहुभाषी शिक्षण तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाए; (3) डिजिटल अवसंरचना का विस्तार किया जाए; (4) जनजातीय समुदायों की नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए; तथा (5) एक मजबूत निगरानी एवं जवाबदेही तंत्र विकसित किया जाए। NEP 2020 का अक्षर नहीं, उसकी आत्मा महत्त्वपूर्ण है। झारखंड के जनजातीय बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक एवं समानतामूलक शिक्षा प्रदान करना न केवल उनका संवैधानिक अधिकार है, बल्कि देश की संपूर्ण प्रगति की बुनियादी शर्त भी है। इस दिशा में ईमानदार प्रयासों की आज सबसे अधिक आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. ASER Centre. Annual Status of Education Report (Rural) 2022. New Delhi: Pratham Education Foundation; 2022.

© 2025 डॉ. सुजीत कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2. Beteille A. The peculiar tenacity of caste and the challenge of education. Econ Polit Wkly. 2010;45(14):41-48.
3. Devi L. Cultural alienation and academic performance of tribal students in Jharkhand: A sociological study. J Tribal Intellect Club. 2021;8(2):112-124.
4. Ekka A. Tribal education in Jharkhand: Issues and challenges. Indian J Soc Sci Res. 2020;17(1):89-98.
5. Govinda R. Who Goes to School? Exploring Exclusion in Indian Education. New Delhi: Oxford University Press; 2011.
6. भारत के महापंजीयक का कार्यालय. भारत की जनगणना 2011: अनुसूचित जनजाति जनसंख्या–झारखंड. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2011.
7. Jhingran D. Hundreds of home languages in the country and many in most classrooms. In: Mohanty A, Panda M, Phillipson R, Skutnabb-Kangas T, editors. Multilingual Education for Social Justice: Globalising the Local. New Delhi: Orient Blackswan; 2009. p. 5-17.
8. झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्. वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22. रांची: झारखंड सरकार; 2022.
9. झारखंड सरकार. झारखंड की जनजातियाँ: एक परिचय. रांची: जनजातीय कल्याण विभाग; 2023.
10. झारखंड शिक्षा विभाग. शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2022. रांची: झारखंड सरकार; 2022.
11. जनजातीय कार्य मंत्रालय. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय: प्रगति रिपोर्ट 2023. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2023.
12. Kumar A. NEP 2020 and tribal education: Prospects and challenges. Contemp Educ Dialog. 2021;18(1):56-78.
13. Ministry of Electronics and Information Technology. Digital India Programme Progress Report 2022. New Delhi: Government of India; 2022.
14. Mohanty AK. The Multilingual Reality: Living with Languages. New Delhi: Orient Blackswan; 2019.
15. Mohanty AK, Panda M, Pal R. Language policy in education and classroom practices in India. In: Menken K, Garcia O, editors. Negotiating Language Policies in Schools: Educators as Policymakers. New York: Routledge; 2010. p. 211-231.
16. Nair S. Girl child education among tribes of Jharkhand: Policy interventions and ground realities. Soc Action. 2022;72(3):44-58.
17. NCERT. National Curriculum Framework for Foundational Stage. New Delhi: National Council of Educational Research and Training; 2021.
18. NCTE. National Curriculum Framework for Teacher Education 2020. New Delhi: National Council for Teacher Education; 2020.
19. नीति आयोग. राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2022.
20. NSDC. Skill Gap Study for Tribal Regions: Jharkhand. New Delhi: National Skill Development Corporation; 2022.
21. Panda M, Mohanty AK. Language matters, so does culture: Beyond the rhetoric of culture in multilingual education. In: Panda M, Mohanty A, editors. Language Matters: Multilingual Education in Tribal Communities. New Delhi: Orient Blackswan; 2009.
22. Ramachandran V, Naorem T. What it means to be a Dalit or tribal child in our schools: A synthesis of a six-state qualitative study. Econ Polit Wkly. 2013;48(44):43-52.
23. Samal JK. Traditional knowledge systems of Jharkhand tribes: Relevance for modern education. Tribal Stud. 2020;7(1):33-47.
24. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय. अनुसूचित जनजाति विकास रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2022.
25. Sharma R. Monitoring NEP 2020 implementation in tribal districts: A framework for evaluation. J Educ Policy. 2021;36(5):712-728.
26. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2020.
27. Singh RK. Infrastructure and access: A study of tribal schools in Jharkhand. J Rural Educ. 2019;34(2):78-92.
28. Sundar N. The Burning Forest: India's War in Bastar. New Delhi: Juggernaut; 2016.
29. Tilak JBG. Education in the Age of Globalisation: The Indian Experience. NIEPA Occasional Paper No. 64. New Delhi: National Institute of Educational Planning and Administration; 2020.
30. TRAI. Telecom Subscription Data as of December 2022. New Delhi: Telecom Regulatory Authority of India; 2022.
31. UDISE+. Unified District Information System for Education Plus Report 2022-23. New Delhi: Ministry of Education, Government of India; 2023.
32. UNICEF India. Situation Analysis of Children in India 2021. New Delhi: United Nations Children's Fund; 2021.
33. Xaxa V. State, Society, and Tribes: Issues in Post-Colonial India. New Delhi: Pearson; 2014.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

© 2025 डॉ. सुजीत कुमार. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/